

## प्रकाशनार्थ / प्रसारणार्थ

### केन्द्रीय करों में हिस्सा बढ़ाने की 15 वें वित्त

### आयोग से की जायेगी मांग— उपमुख्यमंत्री

पटना 26.09.2018

उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बताया कि 30 सितम्बर को एन के सिंह की अध्यक्षता में चार दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे 15 वें वित्त आयोग से केन्द्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी बढ़ाने की पूरी मजबूती से मांग की जायेगी। 12 वें से लेकर 14 वें वित्त आयोग के दौरान केन्द्रीय करों में बिहार की हिस्सेदारी में लगातार कमी आई है।

श्री मोदी ने कहा कि 12 वें वित्त आयोग में जहां केन्द्रीय करों में बिहार की हिस्सेदारी 11.028 प्रतिशत थी वहीं 13 वें 10.917 और 14 वें में 9.787 प्रतिशत रही। 12 वें और 13 वें वित्त आयोग में जहां जनसंख्या को केन्द्रीय करों में हिस्सेदारी के लिए 25 प्रतिशत वेटेज दिया गया था वहीं 14 वें वित्त आयोग में इसे घटा कर 17.5 प्रतिशत कर दिया गया। इसी प्रकार वन क्षेत्र के लिए मिलने वाले 7.5 प्रतिशत के वेटेज का लाभ भी बिहार को नहीं मिल पाया क्योंकि झारखंड के अलग होने के बाद बिहार में नाममात्र का ही वनक्षेत्र रहा।

चार दिवसीय दौरे के दौरान वित्त आयोग 01 अक्टूबर को शहरी व ग्रामीण स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेगा। 03 अक्टूबर को बिहार सरकार की ओर से दिए जाने वाले ज्ञापन पर विस्तृत चर्चा होगी तथा उसी दिन राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी वित्त आयोग की टीम मुलाकात करेगी। 04 अक्टूबर को वित्त आयोग उद्योग—व्यावसाय से जुड़े प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेगा।

गौरतलब है कि अक्टूबर, 2019 तक 15 वां वित्त आयोग देश के सभी राज्यों का दौरा कर अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपेगा जिसके आधार पर 2020—2025 के लिए केन्द्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी निर्धारित की जायेगी।